

न्यूज़ दुड़े

वित्तीय वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, साथ ही केमैन आइलैंड्स (Cayman Islands) से आने वाले धन में 305 प्रतिशत की वृद्धि हुई है

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment: FDI) विगत वित्त वर्ष के 38.74 बिलियन डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2020 में 10 प्रतिशत बढ़कर 42.69 बिलियन डॉलर हो गया है।
- आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण उत्पन्न हुई वैश्विक आर्थिक मंदी और निवेश की चिंताओं के बावजूद, भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वर्ष 2019 में भारत वैश्विक स्तर पर 9वाँ सबसे बड़ा निवेश प्राप्तकर्ता देश रहा है।
- FDI का सर्वाधिक प्रवाह सेवा क्षेत्र (services sector) में प्राप्त हुआ है। इसके अंतर्गत संचार, खुदरा और थोक व्यापार, वित्तीय सेवा, कंप्यूटर एवं व्यावसायिक सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र को 8.15 अरब डॉलर, संचार सेवाओं को 6.83 अरब डॉलर और खुदरा व्यापार को 4.91 अरब डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है।
- केमैन आइलैंड्स से प्राप्त होने वाले FDI में वर्ष 2019–20 के दौरान 305 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 3.49 बिलियन डॉलर हो गया है।
- केमैन आइलैंड्स को टैक्स हेवन क्षेत्र (अल्प कर दर वाले राज्यक्षेत्र) माना जाता है, इसलिए ये निवेश के अनुमार्गन (routing) के लिए सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में से एक बन जाते हैं।
- भारत में FDI प्रवाह के प्रमुख वाहक हैं: FDI मानदंडों में छूट, युवा एवं वहनीय श्रम बल, बाजार का बड़ा आकार, आर्थिक प्रदर्शन, तकनीकी एवं नवाचार क्षमताएं, व्यवसाय करने में सुगमता (Ease of Doing Business: EoDB) के संदर्भ में किए गए सुधार आदि।
- ऑफिशियल रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा भारतीय राज्यों के लिए किए गए एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि EoDB स्कोर में एक प्रतिशत की वृद्धि होने से FDI अंतर्गत हैं 6.32 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होती है।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (World Solar Technology Summit: WSTS) का आयोजन किया गया

- WSTS का उद्देश्य सौर प्रौद्योगिकियों में हुए हालिया विकासक्रम, (लागत व प्रौद्योगिकी के संबंध में), प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, चुनौतियों और इस क्षेत्र से संबद्ध चिंताओं पर चर्चा करने के लिए प्रमुख हितधारकों (शोधकर्ताओं, नवोन्मेषकों आदि) को एकजुट करना है।
- शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष
 - ISA ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विश्व बैंक के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मंत्रालय को देश की "वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड (OSOWOG)" पहल को लागू करने के लिए नोडल एंजेंसी बनाया गया है।
 - ❖ OSOWOG का लक्ष्य 140 देशों को एक कॉमन ग्रिड के माध्यम से जोड़ना है, जिसका उपयोग सौर ऊर्जा के अंतर्गत के लिए किया जाएगा।
 - विश्व भर के शोधार्थियों की सौर ऊर्जा पर लेख प्रकाशित करने के लिए सहायता करने हेतु जर्नल ऑन सोलर एनर्जी (JOSE) लॉन्च की गई है।
- ISA के बारे में
 - ISA एक संघीय-आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है, जिसे COP 21 (वर्ष 2015 का जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फैमवर्क सम्मेलन) के दौरान संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस द्वारा लॉन्च किया गया था।
 - ISA का उद्देश्य वर्ष 2030 तक 1000 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता सृजित करना और सौर ऊर्जा क्षेत्र में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आर्किपित करना है।
 - ISA फैमवर्क समझौते पर 86 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से 68 देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जा चुका है।

कृषि मंत्री ने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर लॉन्च किए हैं और राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission) के लिए लोगो जारी किया गया है

- ये 22 बांस क्लस्टर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, ओडिशा, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड और कर्नाटक राज्यों में लॉन्च किए गए हैं।
- ये क्लस्टर नर्सरी एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और फर्नीचर, अगरबती, खिडकियों में लगाने वाली झिलमिल (Venetian blinds), चॉपस्टिक्स, टूथब्रेश आदि जैसे बांस निर्मित उत्पादों के विकास से संबंधित होंगे।
- इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना, बांस के उपयोग और इसके निर्यात को बढ़ावा देना है।
- बांस के निर्मालिक्षित अनुप्रयोग हैं: निर्माण सामग्री, कृषि उत्पादन, फर्नीचर, संरीत वाद्ययंत्र, खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, बांस आधारित बड़े उद्योग (लुगदी, रेयान आदि), पैकेजिंग इत्यादि में उपयोग करना।
- बांस संवर्धन के लिए किए गए उपाय:
 - भारतीय वन अधिनियम 1927 (Indian Forest Act 1927) के तहत बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाने के लिए वर्ष 2017 में इसमें संशोधन किया गया था। यह गैर-वन क्षेत्रों में बिना किसी अनुमोदन के बांस की कृषि और उसके उत्पादों की कटाई तथा परिवहन करने की अनुमति प्रदान करता है।
 - वर्ष 2018–19 में बांस से संबंधित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (Restructured National Bamboo Mission) प्रारंभ किया गया था।
 - देश में बांस उद्योग की प्रगति सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ आयात नीति (Import policy) में भी परिवर्तन किया गया है।
 - बांस से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने हेतु कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम (Capacity-building and training programmes) आरंभ किए गए हैं।
- भारत बांस संपदा में चीन के पश्चात दूसरे स्थान पर है। बांस के वैश्विक उत्पादन में भारत की भागीदारी 20 प्रतिशत है।

FDI INFLOWS (IN \$ MILLION)

Year	2017-18	2018-19	2019-20
Total	37,366	38,744	42,629
Singapore	9,273	14,632	12,612
Mauritius	13,415	6,570	7,498
The Netherlands	2,677	2,519	5,295
Cayman Islands	1,140	863	3,496
USA	1,973	2,823	3,401

Source: RBI

सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्युओं को वर्तमान 1.5 लाख से घटाकर वर्ष 2025 तक लगभग आधा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

○ सरकार द्वारा वर्ष 2015 में ब्राजीलिया घोषणापत्र (Brasilia declaration) पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत सरकार ने सड़क दुर्घटनाएं एवं इनसे होने वाली मृत्युओं को आधा करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

○ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (National Crime Records Bureau: NCRB) के अनुसार, वर्ष 2019 के दौरान, सड़क दुर्घटनाओं के कुल 4,37,396 मामले दर्ज किए गए थे, जिनके कारण 1,54,732 लोगों की मृत्यु हुई थी।

➢ इसमें यातायात दुर्घटनाओं (43.9 प्रतिशत) के कारण अधिक मृत्यु हुई थी।

○ सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण:

➢ 59.6 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं अत्यधिक गति (over-speeding) के कारण हुई हैं।

➢ 25.7 प्रतिशत दुर्घटनाएं जाखिमपूर्ण और असावधानीपूर्ण ड्राइविंग या ओवरट्रेकिंग के कारण हुई हैं।

➢ 16.8 प्रतिशत दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने, खराब मौसम और यांत्रिक त्रुटि आदि जैसे कारों से घटित हुई हैं।

○ चुनौतियाँ: लाइसेंस जारी करने की भ्रष्ट व्यवस्था, दुर्घटनाओं की निम्नस्तरीय वैज्ञानिक जाँच, राजमार्गों पर पैदल यात्री पार-गमन (क्रॉसिंग) का अभाव आदि।

○ सरकार द्वारा उठाये गये कदम

➢ राजमार्गों पर ब्लैकस्पॉट की पहचान और निवारण [विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank: ADB) द्वारा वित्त पोषित परियोजना]।

❖ ब्लैकस्पॉट: राजमार्गों पर दुर्घटना प्रवण स्थान।

➢ मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Motor Vehicle (Amendment) Act, 2019) के तहत कठोर दंड, दोषपूर्त वाहनों की वापसी और गुड सैरिटेन्स (संकट के समय सहायता करने वाले) की पहचान जैसे प्रावधान किए गए हैं।

➢ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (National Road Safety Policy): इसे वर्ष 2010 में अनुमोदित किया गया था। यह सुरक्षित सड़क अवसरंचना, वाहन एवं वाहन चालक की सुरक्षा आदि के लिए नीतिगत पहल की रूपरेखा निर्धारित करती है।

➢ राजमार्गों से खतरनाक बिंदुओं को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित सड़क योजना (Pradhan Mantri Surakshit Sadak Yojana) का संचालन किया जा रहा है।

तमिलनाडु ने त्रिभाषीय फॉर्मूले (three-language formula) के विरोध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है

- तमिलनाडु सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में हिं-भाषीय नीति (तमिल और अंग्रेजी) को जारी रखा जाएगा।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP) के तहत त्रिभाषीय फॉर्मूले को प्रस्तावित किया गया है। इसके अंतर्गत यह अनुशंसा की गई है कि सभी छात्र इस फॉर्मूले के तहत अपने विद्यालय में तीन भाषाएं सीखेंगे।
 - > जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, तथा अंग्रेजी को उनमें पृथक् भाषा माना जाएगा।
 - > हालांकि इसमें उल्लिखित है कि राज्य, क्षेत्र व छात्र दो भारतीय भाषाओं के बचन हेतु स्वतंत्र होंगे।
- इसके अतिरिक्त, नवीन NEP कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने का सुझाव देती है।
- त्रिभाषीय फॉर्मूला प्रथम बार वर्ष 1968 में केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था तथा इसे वर्ष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया था। इस योजना का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना था कि छात्र अधिक भाषाएं सीख सकें।

अन्य सुर्खियाँ

पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी (पैज़) (Partnership for Action on Green Economy: PAGE)	<ul style="list-style-type: none"> ○ PAGE को वर्ष 2013 में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, आय और रोज़गार का सृजन करने, निर्धनता एवं असमता को कम करने तथा राष्ट्रों द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं के पारिस्थितिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक नीतियों व प्रथाओं का धारणीयता के अनुसार पुनर्निर्धारण करने की दिशा में राष्ट्रों का समर्थन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ○ यह साझेदारी सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य क्रमांक-8 को प्राप्त करने में देशों को सहायता प्रदान करने का प्रयोजन रखती है। SDG-8 में सभी के लिए "संधारणीय, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोज़गार तथा सम्मानीय कार्य को बढ़ावा देना" शामिल है। ○ PAGE, संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियों यथा— संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को एक मंच प्रदान करता है।
ई-किसान मंडी (e-Kisan Mandis)	<ul style="list-style-type: none"> ○ प्रथम ई-किसान मंडी का परिचालन पुणे में प्रारंभ किया गया है। यह भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED) की एक पहल है। ○ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) [जो कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) पर केंद्रित है] के विपरीत ई-किसान मंडियां कृषि उत्पादों के व्यापार के लिए किसानों, कृषि-उत्पादकों, व्यापारियों और छोटे खरीदारों को एक साझा मंच प्रदान करती हैं। ○ ये एक हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत कार्य करेगी, जिसमें NAFED के स्वामित्वाधीन भूमि ही संबंधित क्षेत्र में कृषि उत्पाद कपनियों (FPCs) हेतु हब के रूप में आवंटित होंगी।
किरण (KIRAN)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, कष्ट (Distress) निवारण, मानसिक स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई एक 24x7 टोल-फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार हेल्पलाइन है। ○ यह हेल्पलाइन 13 भाषाओं में सेवाएं प्रदान करेगी। ○ इसे सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है।
थाईलैंड ने "क्रा-नहर परियोजना" रद्द की (Thailand scraps Kra Canal Project)	<ul style="list-style-type: none"> ○ हाल ही में, थाईलैंड ने चीन द्वारा प्रस्तुत क्रा-नहर के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है। ○ क्रा-नहर के प्रस्ताव के तहत थाईलैंड में क्रा-स्थलमरुमध्य (Isthmus) के माध्यम से 120 किलोमीटर की विशाल नहर का निर्माण किया जाना था। <ul style="list-style-type: none"> > यह जलमार्ग अंडमान सागर को थाईलैंड की खाड़ी से जोड़ेगा तथा साथ ही, मलका जलमरुमध्य से दूर नौवहन का मार्ग परिवर्तन कर एक समुद्री लघु मार्ग प्रदान करेगा। ○ इस परियोजना के माध्यम से चीन का उद्देश्य मलका जलमरुमध्य का उपयोग न करके समुद्री आवागमन के अन्य विकल्प का प्रयोग करना है, जिससे मलका दुष्प्रिया (Malacca dilemma) का समाधान किया जा सके।
ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में धरातलीय ओजोन की सांद्रता में कमी (Low ozone over Brahmaputra River Valley)	<ul style="list-style-type: none"> ○ शोधकर्ताओं ने पाया है कि उत्तर-पूर्व के इस क्षेत्र में धरातलीय ओजोन (ground-level ozone) की सांद्रता अन्य शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है। ○ क्षोभमंडलीय (Tropospheric) या धरातलीय ओजोन का निर्माण नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स (NO_x) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (volatile organic compounds) के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा होता है। ○ कारों, विद्युत संयंत्रों, रिफाइनरी और अन्य स्रोतों से उत्पर्जित प्रदूषकों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया इसकी सांद्रता में वृद्धि करती है। इस प्रकार इसकी बढ़ी हुई सांद्रता मानव स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
उर नदी, मध्य प्रदेश (Ur river, Madhya Pradesh)	<ul style="list-style-type: none"> ○ नागरिक समाज के सदस्यों और राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा भूमिगत जल स्रोतों के पुनर्भरण (मृदा जल अवशोषण सुनिश्चित करते हुए और वर्षाजल के व्यर्थ प्रवाह को कम करते हुए) के माध्यम से उर नदी को पुनर्जीवित करने हेतु एक संयुक्त प्रयास किया गया है। <ul style="list-style-type: none"> > भूमिगत जल स्रोतों के पुनर्भरण हेतु प्रत्येक लघु मू-खंड पर गर्तों या खेत-तालाबों का निर्माण किया गया है। ○ उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में ओडी नदी (Ody river) के संरक्षण के दौरान भी जमीनी स्तर पर इसी प्रकार की भागीदारी दृष्टिगोचर हुई थी।
व्हाइट ग्रब (श्वेत गिडार) (Holoëtrichia serrata) कीट लार्वा (White grub (Holotrichia serrata) insect larvae)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह एक कृषि कीट है, जो गन्धे की फसल को क्षति पहुंचाता है। यह कीट गन्धे की जड़ों का निष्कर्ष करता है, जिसके कारण पौधे के लिए नमी और पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। ○ इससे पत्तियों में पीलापन आ जाता है और वे गिरने लगती हैं तथा प्रोट्रो (shoot) के आधार को क्षति पहुंचती है। ○ शुरुआत में इन कीटों ने गन्धे और मूँफाफी की फसलों को प्रभावित किया था, परन्तु अब ये कीट सोयाबीन, कपास तथा हल्दी की फसलों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ○ हालांकि व्हाइट ग्रब संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध हैं।
झारखंड मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री श्रमिक (कामगारों के लिए शहरी रोज़गार मंजूरी) योजना को स्वीकृत प्रदान कर दी है {Mukhyamantri SHRAMIK (Shahri Rozgar Manjari For Kamgar)}	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह योजना शहरी अकुशल श्रमिकों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोज़गार कार्य की गारंटी प्रदान करेगी। ○ इस योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के समान ही यदि राज्य 100 दिन कार्य देने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। ○ 18 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक, जो नागरिक निकाय द्वारा संचालित क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 (8 सितंबर) International Literacy Day 2020 (8th September)	<ul style="list-style-type: none"> ○ इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य मानवीय गरिमा और मानवाधिकार के आलोक में साक्षरता के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। ○ यूनेस्को (UNESCO) द्वारा वर्ष 1966 में अपने सम्मेलन के 14वें सत्र के दौरान 8 सितंबर को औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई थी।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in

